

# Newspaper Clips

## March 20, 2013

Times of India  
20/04/2013

P-12

### 'Dead' IIT satellite comes alive

Srinivas Laxman | TNN

**Bangalore:** What was given up as dead, turned out to be alive! The one that sprang a recent surprise was India's first IIT-made student satellite, Jugnu, a product of the students and staff of IIT-Kanpur. The three-kg student satellite was launched on October 12, 2011, along with SRMSat of SRM University in Chennai and VesselSat-1 of Luxembourg. The main satellite was the Indo-French Megha-Tropiques.

Speaking from Kanpur on Friday chief co-ordinator of Jugnu, NS Vyas, said mission life of satellite was one year. "We had stopped tracking it. But when we came to know from Nitte Amateur Satellite Tracking Centre in Bengaluru it was after all still alive we were thrilled," he said.

*For the full story, log on to  
[www.timesofindia.com](http://www.timesofindia.com)*

अमेरिकी युवा कर्ज लेकर पढ़ने व अपने पैरों पर खड़ा होने में गर्व महसूस करते हैं

# हायर एजुकेशन इंडस्ट्री है यहां

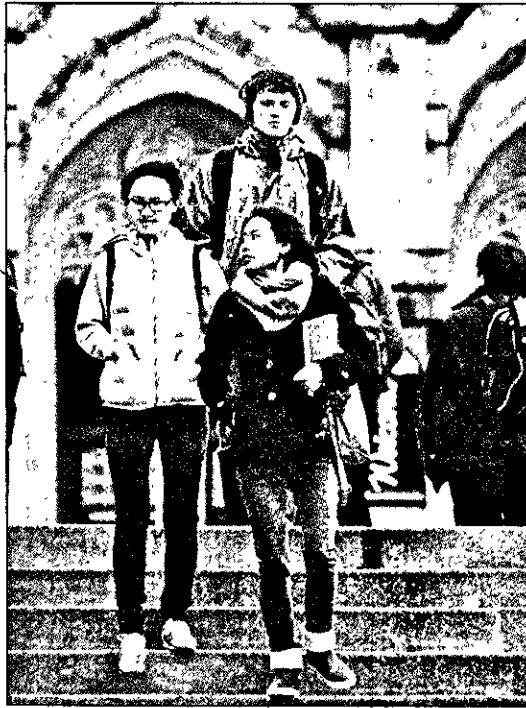
न्यू यार्क से ललित बंसल II

अमेरिका में लॉ और मेडिकल - दो हाइली पेड जॉब माने जाते हैं। वहां लॉ के ग्रेजुएशन में सात से आठ साल लग जाते हैं और मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए ग्यारह साल और कम से कम एक से डेढ़ करोड़ रुपये। इन दोनों पाठ्यक्रमों के लिए येल, हार्वर्ड और स्टेनफोर्ड की गणना सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज में होती है। लेकिन भारत की तरह यहां ऐसा नहीं है कि पैरेंट्स अपने बेटे या बेटों को लॉ अथवा मेडिकल या एमआईटी से ग्रेजुएशन कराने के लिए अपना घर-बार अथवा कारोबार दांव पर लगा दें।

इन डिग्रियों के अलावा यहां ऐसी कितनी ही डिग्रियां और पाठ्यक्रम हैं जहां रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। इसके लिए अमेरिका में बच्चों की स्कूली शिक्षा की नींव को मजबूत किए जाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क होती है। और अनिवार्य शिक्षा के लिए घर के समीप काउंटी स्तर पर प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल होते हैं। इनके सिलेबस का निर्धारण भी समय-समय पर फेडरल सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार काउंटी प्रबंध मंडल करता है।

एक बार सिलेबस तय हो जाने के बाद हेड मास्टर की पूरी जिम्मेदारी होती है और वह अपने टीचरों से उम्मीद रखता है कि वे छात्रों के लिए अपेक्षित ग्रेड और रिजल्ट सुनिश्चित करेंगे। इसमें टीचर और पैरेंट्स की भूमिका बहुत अहम होती है। टीचर अपनी क्लास के बच्चों के ग्रेड पर ही नहीं बल्कि क्लास से बंक मारने वाले बच्चों पर भी नजर रखते हैं, विशेषकर हाई स्कूल में। वे अभिभावकों से बराबर संपर्क बनाए रखते हैं। किसी भी शिक्षक के लिए उसकी क्लास का शत-प्रतिशत रिजल्ट ही उसकी सीमित अनुबंधित नौकरी का आधार माना जाता है। स्कूली शिक्षा में पैरेंट्स की काफी सक्रिय भूमिका रहती है। अक्सर देखने में आया है कि अपने-अपने क्षेत्र में निपुण अभिभावक हफ्ते अथवा पखवाड़े में एक बार स्कूल में क्लास लेने में अपना सम्मान मानते हैं। पैरेंट्स और टीचर असोसिएशन का प्रेजिडेंट कोई अभिभावक ही होता है। इन काउंटी स्कूलों के साथ-साथ वहां प्राइवेट स्कूल भी होते हैं जो अपेक्षाकृत महंगे होते हैं। कुछ वर्षों से टीचरों की लेबर यूनियन बन गई हैं, जो नौकरी के अनुबंध की शर्तों को लेकर काउंटी के खिलाफ आवाज उठाने लगी है।

कॉलेज एजुकेशन में पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य यहां व्यावसायिक होता है। अमेरिका में शिक्षा का मकसद भारत की तरह मात्र डिग्रियों की संख्या बढ़ाना



नहीं होता, बल्कि उसे रोजगार के लायक बनाना होता है। इसलिए उनके सिलेबस भी उसी तरह से तैयार किए जाते हैं। इसके लिए अमेरिका में प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही तरह के यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं। स्टूडेंट्स दो वर्षीय अथवा चार वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स के चयन में पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। यहां पब्लिक और प्राइवेट -दोनों ही तरह के यूनिवर्सिटी कॉलेजों में इन ग्रेजुएशन कोर्स की इतनी भरमार होती है कि छात्र अपनी शिक्षा, रुचि और आर्थिक क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। यहां के मूल निवासियों में श्वेत अथवा अश्वेत वर्ण के नौजवान किसी बड़ी डिग्री के पीछे भागने की बजाय अपनी स्वतंत्र और स्वाभिमान पूर्ण जिंदगी जीने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। इसलिए स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद पैरेंट्स भी अपने बच्चों को कॉलेज शिक्षा के लिए निश्चित रहते हैं। भारत की तुलना में यहां बैंक और फेडरल सरकार की ओर से दिए जाने वाले लोन आसानी से और सस्ती ब्याज दर पर मिल जाते हैं। अमेरिका में उच्च शिक्षा पर ब्याज दर भारत की तुलना में करीब एक चौथाई है और ऋण किसी जायदाद अथवा जमा राशि के दस्तावेजों को जमा कराए बिना सहज रूप से मिल जाते हैं।

फेडरल सरकार हायर एजुकेशन के लिए बैंक दर से भी सस्ती दरों पर ऋण सुविधा जुटाती है। अश्वेतों और लतिन अमेरिकी लोगों की पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमजोर होने तथा घरेलू परिवेश शिक्षा-दीक्षा

के अनुकूल नहीं होने के कारण इनके ज्यादातर युवा स्कूली शिक्षा के बाद रोजगार की तलाश में जुट जाते हैं। हां, प्रवासी भारतीय अभिभावकों की जरूर यह कोशिश रहती है कि उनका बेटा या बेटा स्टेनफोर्ड मेडिकल स्कूल से मेडिकल या हार्वर्ड से लॉ या एमआईटी से ग्रेजुएशन कर एक नामी इंजीनियर बने।

पूँजीवादी व्यवस्था होने के नाते अमेरिका में यूनिवर्सिटी और इससे संबद्ध कॉलेज प्राइवेट होते हैं। ये न तो सरकार से ग्रांट अथवा कोई अनुदान राशि मांगते हैं और न ही इन पर सरकार की ओर से कोई बंधन ही होता है। इसलिए अपने छात्रों से सेमिस्टर अथवा सालाना फीस भी मोटी लेते हैं। एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी की पहचान उसकी फीस और फैकल्टी को मिलने वाले वेतनमान से लगाई जाती है। अमेरिका में उच्च शिक्षा एक उद्योग है। यहां चीन से हर साल करीब दो लाख युवा हायर एजुकेशन के लिए आते हैं, भारत से सवा लाख युवा और दूसरे देशों से भी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स यहां हर साल आते हैं। इससे अमेरिका को प्रतिवर्ष बीस अरब डॉलर की मुद्रा मिलती है। इसके विपरीत भारत में आईआईटी अथवा आईआईएम या सरकारी अनुदान राशि पर चल रहे मेडिकल कॉलेज ढांचागत सुविधाओं में अपेक्षित सुधार करने की बजाय न्यूनतम सुविधाओं और सामान्य वेतनमान पर न्यूनतम फैकल्टी से काम चलाने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं।

अमेरिका में मेडिकल शिक्षा के लिए पहले चार वर्ष साइंस ग्रेजुएशन और फिर चार वर्ष का समय मेडिकल स्कूल में व्यतीत करना पड़ता है। इसके लिए एक छात्र को पहले साइंस ग्रेजुएशन और फिर मेडिकल स्कूल के लिए कॉलेज फीस, बोर्डिंग और खानपान एवं पुस्तक आदि के लिए करीब एक करोड़ से डेढ़ करोड़ रुपये का ऋण लेना पड़ता है। मेडिकल प्रैक्टिस के लिए तीन साल की रेसीडेंसी अनिवार्य है जिसके लिए विशेष परीक्षा देनी होती है। इसी तरह लॉ अथवा वकालत की डिग्री के लिए पहले चार साल की ग्रेजुएशन के बाद तीन साल वकालत की डिग्री के लिए लगाने पड़ते हैं। इसके लिए लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट देना अनिवार्य है। इसके विपरीत भारत में हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद मात्र साढ़े पांच साल में एक छात्र मेडिकल शिक्षा पूरी कर एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर चिकित्सक बन जाता है तो वकालत की डिग्री पांच साल में मिल जाती है। लेकिन अमेरिका में छात्रों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ ढांचे में जो एक्सपोजर मिलता है, उसके लिए भारत में शिक्षित अच्छे प्रफेशनल भी तरस जाते हैं।

Mint ND 20/04/2013

p-10

## EDUCATION

# Govt's e-Pathshala scheme set to begin

**New Delhi:** The ambitious e-Pathshala programme of the government, seeking to create quality content across disciplines at the post-graduate level, is set to kick off with the University Grants Commission (UGC) asking universities throughout the country to contribute to the exercise.

The initiative, approved by the ministry of human resource development in 2011, proposes to develop e-content in 77 subjects across disciplines and the material will be made available to both teachers and students in the form of open online courses. **PTI**

HT Kolkata

# IIM-Calcutta to offer kayaking on campus

**Mou Chakraborty**

■ [Mou.Chakraborty@hindustantimes.com](mailto:Mou.Chakraborty@hindustantimes.com)

**KOLKATA:** Before helming corporate giants, B-school students should learn a thing or two about teamwork and management by taking to the oars right away, the Indian Institute of Management, Calcutta (IIM-C) feels, having decided to offer kayaking as an activity on campus.

Kayaks, relatively narrow boats propelled by rowing, were first used by Eskimos thousands of years ago and are of popular leisure utility today. India, however, is yet to embrace the sport, professionally or recreationally.

But the IIM-C, which has as many as seven lakes in its 135-acre campus, sees kaya-

king as not only a new sport for its students, but also a tool to enhance cohesiveness in groups of people. The campus has chosen the lake in front of the recently-constructed lake view hostels at the rear of the campus.

“We are constructing a jetty, a boat house with storage and changing rooms. In few months we should be able to offer kayaking facility to our students,” said Lt Col Alok Chandra, chief administrative officer of IIM-C.

“No institute in India has this facility. Since IIM-C has the luxury of seven lakes inside its campus, we thought of becoming the first,” lieutenant colonel Chandra said.

HT New Delhi

# Activists demand more teeth for whistleblower bill

**HT Correspondent**

■ letters@hindustantimes.com

**NEW DELHI:** A civil society group on Friday demanded key changes in the bill to protect whistleblowers, including widening its scope to bring all categories of public servants and private sector employees under its purview.

The National Campaign for People's Right to Information, after day-long consultations with the families of some of the whistleblowers, asked the government to make the definition of victimisation clear in the bill.

The Whistleblowers Protection Bill was passed by the Lok Sabha in December 2011 and is pending before the Rajya Sabha. The bill listed for introduction on Monday aims to provide protection to whistleblowers, both in the government and private sector.

A few case studies show why the ambit of the law should be widened.

Ashok Khemka, an IAS officer, has been transferred over 40 times during his service for exposing corruption. Even though he does not describe himself as a whistleblower, Khemka said the transfers were a routine affair.

A doctorate in computer science from the Tata Institute of Fundamental Research Mumbai and alumni of IIT-Kharagpur, Khemka said the best way to fight corruption was by remaining in the system.

In March, Ram Thakur and



■ Senior IAS officer and whistleblower Ashok Khemka during a public hearing on Whistle Blowers protection bill and Grievance Redress Bill at Constitution Club in New Delhi on Friday. ARIJIT SEN / HT PHOTO

his nephew were returning on a bicycle from a court in Bihar when a group of six motorcycle-borne persons surrounded them and shot Thakur on the orders of the son of village pradhan Rajesh Kumar Sahani.

Thakur had used the Right to Information Act (RTI) to expose corruption in the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme by the village pradhan.

Anti-graft crusader Nandi Singh, hailing from Assam, was killed in an attack in September 2012. He had exposed corruption in the Public Distribution System (PDS) through the RTI.

His wife Saorthi Singh, who also sustained injuries in the attack, recalled how the family was troubled for seeking information on the PDS. Of the eight accused, only four were arrested

and later released on bail.

In 2011, Mahabir Prasad filed an RTI to know why he and others were not receiving old age pension. This earned him the wrath of the village council head Dharampal Malik. A brawl ensued in which his daughter-in-law died.